नई दिल्ली नगरपालिका की बसें

427. **श्री गोविन्दा मुण्डा :**
श्री सरत चार :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने 26 लाख रु० की लागत पर 20 बसें, 10 बसें, 1974, और 10 बसें 1975 में, खरीदी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बसें 50, 52 और 630 रूटों पर चलाई जा रही थीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये बसें नई दिल्ली नगरपालिका की मंदिर मार्ग वर्कशाप में बिना किसी कारण के फालतू खड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा इन बसों को तत्काल सड़क पर लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने 22.36 लाख रु० की लागत से न कि 26 लाख रु० की लागत से, 20 बसें खरीदीं।

(ख) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम के साथ हुए करार के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका ने 40, 50, 52 और 630 के रूटों पर 20 बसों को चलाया। नई दिल्ली नगरपालिका ने 28-8-78 से अपनी बसों को दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन से हटा लिया है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने 2-9-78 को 9 बसें बेच दी और 6 बसें अपने शिक्षा संस्थानों के प्रयोग के लिए रख ली हैं। शेष 5 बसों को भी बेचने का विचार है, जिनके लिए फिर निविदाएं मांगी गयी हैं।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका ने 23-6-78 को निश्चय किया कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका जिन बसों को चला रही है, उन्हें बन्द कर दिया जाय क्योंकि उनको चलाना अलाभप्रद था। तदनुसार बसें 28-8-78 से हटा ली गयीं। बसों को दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत फिर चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

'दिल्ली मर्डर्स दैट रिमेन अनसाल्वड' शीर्षक समाचार

428. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितम्बर, 1978 के 'सण्डे स्टैण्डर्ड' में 'दिल्ली मर्डर्स रिमेन अनसाल्वड' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) ऐसे पुराने मामलों को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). समाचार पत्र की रिपोर्ट में बताए गए हत्या के मामलों की पूर्ण रूप से जांच की गई थी किन्तु क्योंकि कोई सुराग उपलब्ध नहीं हो रहा था इसलिए उनको लापता मामलों के रूप में भेज दिया गया। जब कभी कोई नया सुराग प्राप्त होगा तो मामलों को पुनः शुरू किया जाएगा।

Expenditure on construction of heavy Water Plants

429. DR. SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the estimated expenditure likely to be incurred on the construction of each of the four heavy water plants in the country;

(b) the production capacity of each plant; and

(c) whether the work on these plants has been going on as scheduled and if not, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The estimated expenditure likely to be incurred on the construction of four Heavy Water Plants and the capacity of production of each of these Heavy Water Plants are given below:—

Name of the plant	Estimated Expenditure (Rs in lakhs)	Capacity
1 Heavy Water Plant (Kota)	5592·00	100 tonnes/year
2 Heavy Water Plant (Baroda)	3417·00	67·2 tonnes/year
3 Heavy Water Plant (Tuticorin)	3741·00	71·3 tonnes/year.
4 Heavy Water Plant (Talcher)	5075·00	62·7 tonnes/year

(c) The scheduled dates for completion of these Heavy Water Plants could not be adhered to due to various reasons. The technology of production of heavy water is new and complex and processes adopted for these plants are being used for the first time in India. This factor and the delay in the supply of equipment from indigenous and foreign sources, problems in transportation of certain heavy equipments, failure of some of these equipments, interruptions in the supply of power and synthesis gas and events like strikes are the main reasons for the delay in commissioning of the Heavy Water Plants. The production of heavy water at Baroda plant had started on July 4, 1977 but due to an accident that occurred on December 3, 1977 the plant had to be shut-down. The plant is now expected to be back on production in December, 1979. The production of heavy water was started at Tuticorin plant on July 17, 1978.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन न किया जाना

430. श्री वी० जी० हांडे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कंट्रोल का कपड़ा बनाने वाली मिलों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है ;

(ख) अब ऐसे कपड़े का उत्पादन किस प्रकार किया जायेगा ;

(ग) क्या जन-साधारण को कुछ राहत देने के लिये कंट्रोल का कपड़ा बनाने की कोई नई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा मांईति) (क) से (घ). 1 अक्टूबर, 1978 से प्रभावी नई वस्त्र नीति के अनुसार मिल क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन लक्ष्य 4000 लाख वर्ग मीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। नियंत्रित कपड़े का उत्पादन दोनों ही क्षेत्र की मिलों अर्थात् राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा किया जाएगा। नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की भूमिका व्यापक बना दी गई है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित की जाने वाली नियंत्रित कपड़े की मात्रा निर्धारित कर दिए जाने के बाद जो उत्पादित की जाने वाली कुल मात्रा का करीब आधा होगा। शेष भाग का उत्पादन करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर तथा इस शर्त पर कि कपड़ों का मूल्य राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित उसी प्रकार के कपड़ों के मूल्य से अधिक नहीं होगा, निजी क्षेत्र की मिलों को ठेका दिया जायेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र को मिलों द्वारा उत्पादन में हुई किसी प्रकार की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंपी गई है इस प्रकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किए जाने वाले कुल उत्पादन की मात्रा समय-समय पर निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर निर्भर करेगी।

Bus Sheds in the Capital

431. SHRI DALPAT SINGH PARASTE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) how many bus stops in the Capital still do not have the sheds for the passengers to wait;

(b) the main reasons for not providing sheds at bus stands; and